(i) हसन इकबाल समिति:

श्री हसन इकबाल रेलवे के सेवानिवृत्त वित्तायुक्त की अध्यक्षता में लागत/लाभ केन्द्रों का पता लगाने और लेखा प्रणाली का विकास करने तथा वित्तीय सूचना प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए। समिति ने अपनी वैचारिक रिपोर्ट दिसंबर 1994 में प्रस्तुत की है।

(ii) के॰ वी॰ गुप्ता-नारायण समिति:

उन व्यक्तियों को तैयार करने के लिए जो केवल मंडल रेल प्रबंधक, अपर महा प्रबंधक, महाप्रबंधक और सदस्य जैसी सामान्य प्रबंधन स्थितियों पर तैनात होंगे, विकास तथा प्रवरण प्रक्रिया सहित एक एकीकृत भारतीय रेलवे सेवा के सृजन के लिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग-I प्रस्तुत कर दिया है।

(iii) पौलोस समिति:

श्री ए.वी. पौलोस, रेलवे के सेवानिवृत्त वित्तायुक्त की अध्यक्षता में भारतीय रेलों की पूंजी पुनर्संरचना और यातायात में सकारात्मक फेर-बदल और लागत प्रणाली की समीक्षा के लिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग-I दिसम्बर 1994 में प्रस्तुत किया है।

दिल्ली रेलवे डिवीजन में सरकारी आवास के लिए बनी प्रतीक्षा सूची

7217. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी रिकार्ड के अनुसार कितने रेल कर्मचारियों ने सरकारी आवास के लिए श्रेणी-वार दिल्ली में भवन अधीक्षक (आवास) दिल्ली डिवीजन विभाग, रेलवे के पास 30 अप्रैल 1995 तक अपना पंजीकरण करवाया था और इस संबंध में उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) किस वर्ष तक की विभिन्न श्रेणियों की प्रतीक्षा सूचियों को निपटा दिया गया है?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ):

(क) आवास की कोटि	पंजीकृत 30.4.95 को कर्मचारियों की संख्या
अनिवार्य	20,331
गैर-अनिवार्य	11,424

(ख) आवास की टाइप	कोटि	जिस तारीख तक प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
टाइप-I	गैर-अनिवार्य	19.12.58
	अनिवार्य	15.5.91
टाइप-II	गैर-अनिवार्य	31.7.59
	अनिवार्य	21.1.84
टाइप-III	गैर-अनिवार्य	4.11.72
	अनिवार्य	17.4.85
टाइप-IV	गैर-अनिवार्य	9.4.84
	अनिवार्य	22.2.85

रेल विभाग को आवश्यक सेवा के अंतर्गत लाया जाना

7218. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अधीन किन-किन विभागों को आवश्यक सेवा के अंतर्गत रखा गया है; और

(ख) क्या सरकार ने रेल आरक्षण विभाग को भी इस सेवा के अंतर्गत शामिल किया है?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) और (ख) रेल मंत्रालय के अधीन विभागों का अनिवार्य तथा गैर अनिवार्य के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं है, तथापि, क्वार्टरों के आवंटन के प्रयोजनार्थ कर्मचारियों को, अनिवार्य तथा गैर अनिवार्य कोटियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश मौजूद हैं जो कि स्थानीय हालत तथा कर्मचारी के संबंधित विभाग का ध्यान किए बिना उसको रेलवे की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं।

Decrease in the demand of wagons

7219. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state.

(a) whether it is a fact that demands of wagons has decreased during the last ten years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the demand of wagons in the country during 1984-85 to 1994-95, year-wise?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C K. JAFFER SHARIEF); (a) and (b) The demand for wagons is need-based and is related to transported output. The reduction in demand

is due to the transport output having declined, due to drop in lead, improved asset utilisation and less traffic offering.

(c) Loes not arise.

Amount due to Maharashtra for Deployment of G.R.P.

7220. SHRI V.N. GADGIL: Will the Minister of the RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the amount due from therailways to the Government of Maharashtra on account of deployment of staff from the State Police on the Central Railway, Western Railway, South Central Railway and South Easthem Railway;

(b) whether ex-post facto sanction of the Railway Administration to the post of G.R.P. created after 1st. April, 1979 has not yet been accorded by the Railway Authorities in spite of the request made by the Government of Maharashtra letter of 12th July, 1991 and subsequent reminders thereafter;

(c) whether the ban on the payment of the post of G.R.P. has not yet been lifted by the Railway Board, in spite of the submissions of Audited Certificates by the Government of Maharashtra; and

(d) what are the reasons for delay in taking action in the matter.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF); (a) The outstanding amount due to Maharashtra State Government from Railways as on 31-3-95 is as under:—

(i) Central Railway	Rs. 14.51 Crs.
(ii) Western Railway	Rs. 8.67 Crs.
(iii) South Central Railway	Rs. 1.48 Crs.
(iv) South Eastern Railway	Rs. 0.35 Crs.
	(As on 31.12.94)

(b) No ex-post facto sanction of the Railways has been accorded as these were created without prior approval of Railway Administration.

(c) and (d) Ban has been lifted and interim orders have already been issued in March, 95 to clear 50% of outstanding dues as on 31.3.95.

इलाहाबाद जंक्शन पर आरक्षण लिपिकों का लम्बे समय से पदस्थापित रहना

7221. श्री लक्खीराम अग्रवाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रेलवे के इलाहाबाद जंक्शन स्थित आरक्षण/पूछताछ कार्यालय में लगातार गत 10-15 वर्षों से पदस्थापित लिपिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों ने लम्बे समय से एक ही स्थान पर कार्य करते रहने से अपना एकाधिकार कायम कर रखा है और इस कारण लोगों के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार करते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इन आरक्षण लिपिकों को स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार एक ही स्थान पर लम्बे समय से पदस्थापित आरक्षण लिपिकों को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ताकि उनका एकाधिकार समाप्त हो सके; और

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सीº केº जाफर शरीफ): (क) से (ङ) इस आशय के अनुदेश पहले से ही मौजूद है कि पूछताछ एवं आरक्षण क्लर्कों सहित संवेदनशील पदों पर कार्यरत रेल कर्मचारियों का प्रत्येक चार वर्षों पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर या उसी स्टेशन पर एक सीट से दूसरी सीट पर स्थानांतरण कर दिया जाए जिससे कि निहित स्वार्थ को बढ़ावा न मिल सके, इलाहाबाद जंक्शन के आरक्षण/ पूछताछ कार्यालय में इन अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, वहां तैनात 56 कर्मचारियों में से मात्र एक कर्मचारी 10 वर्षों से अधिक समय तक इलाहाबाद जंक्शन पर कार्यरत है। अवधिक स्थानांतरण योजना के आधार पर उसे भी एक सीट से दूसरी सीट पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

Poor quality of food supplied in trains/ Railway Stations in Kerala

7222. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government ate aware that food supplied in the trains and Railway Stations in Kerala is poor in quality and heavy in price; and

(b) if so, what steps are being taken to improve the quality of the food?